सुपरफास्ट खबरें

नेहरू युवा केंद्र से जोड़े जाएंगे युवा

संवाददाता हरिद्वार। नेहरू युवा केंद्र की वार्षिक कार्ययोजना के लिए जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को विकास भवन में हुई। इसमें केंद्र से बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने की योजना बनाई गई। बैठक में समिति सदस्यों की ओर से मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना पर चर्चा की गई। चालू वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से अब तक के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। जिला युवक समन्वयक अंकिता कोठियाल ने जिला प्रशासन और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर और युवाओं को जोड़ने की योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है।

नशा रोकने के लिए अब बॉर्डर पर होगी चेकिंग

संवाददाता रुड़की। अब शहर में नशा कारोबारियों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। स्कूल कॉलेज के आसपास नशे की खेप की बिक्री करने के साथ ही इस कारोबार से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जाएगी। इसके अलावा रात को बॉर्डर तथा शहर और देहात के हर प्वाइंटों पर चेकिंग होगी। एसएसपी ने लंबित लूट और चोरी की घटनाओं के वर्कआउट करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को एसएसपी डी सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने एसपी देहात कार्यालय में पुलिस की बैठक ली। एसएसपी ने शहर और देहात में नशे की खेप की बिक्री करने वाले नशे के सौदागारों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए।

कर्णप्रयाग संकुल बना शरद शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का विजेता

संवाददाता गौचर। क्रीड़ा मैदान में प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल की तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन किया गया। संकुल कर्णप्रयाग 152 अंकों के साथ प्रथम, पनाई द्वितीय व देवल संकुल तीसरे स्थान पर रहा। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पनाई से छात्र प्रवीण नायक विजेता रहे। प्रतियोगिता के प्राथमिक वर्ग की कबड्डी में कर्णप्रयाग संकुल विजेता व पनाई उपविजेता रहा। सुलेख हिन्दी जूनियर वर्ग में कोलाडुंग्री की हिमानी प्रथम, लंगासू की परी शाह व बिरेंद्र दूसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में तेफना संकुल की दीपा व ऋतिका ने क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान हासिल किया।

उत्तराखंड में बेचा जा रहा मीट वैध स्लाटर हाउस का है या नहीं

हाई कोर्ट ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउस पर पूछा सवाल

संवाददाता

नैनीताल। हाई कोर्ट ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउसों में खुलेआम मीट बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए पूछा है कि जो मीट बिक रहा है, वह वैध स्लाटरों का है या नहीं, इसकी जांच कर 22 सितंबर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से मीट कारोबारियों व मीट की दुकानों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है, ताकि यह पता लग सके कि मीट वैध स्लाटर हाउस का है या अवैध का। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे आर्डर प्रस्तुत करने को कहा था, मगर सरकार आदेश पेश नहीं कर सकी।

पूर्व में कोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउसों को बंद करने के आदेश पारित किए थे। कोर्ट ने कहा था कि खुले में किसी तरह के जानवरों को न काटा जाए। जिसके बाद पूरे प्रदेश के स्लाटर हाउस बंद हो गए थे। कोर्ट के इस

आदेश को मीट कारोबारियों द्वारा विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। उनका कहना था कि कोर्ट ने नौ दिसंबर 2011 को एक आदेश पारित कर सरकार को मानकों के अनुसार स्लाटर बनाने को कहा था मगर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिस कारण मीट कारोबारियों को नुकसान हो रहा है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में जिलाधिकारियों से 22 सितंबर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

प्रौद्योगिकियों को जमीनी स्तर पर उपयोग में लाएं

रुड़की। **संवाददाता**

केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआइ) रुड़की में उत्तराखंड के इंजीनियरों के लिए बहु आपदा प्रतिरोधी आवास तथा पर्यावास विषय पर आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हो गया।

इस मौके पर प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सुवीर सिंह ने कहा कि सीएसआइआर ने पूरे भारत में आपदा प्रतिरोधक (डिजास्टर रेसिस्टेंट) आवास बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसे पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के पांच दिन प्रतिभागियों को संस्थान में भवन निर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जिन्हें वे अपने कार्यक्षेत्र में जाकर जमीनी स्तर पर उपयोग में लाएं, ताकि जनता को भी इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि बहु आपदा प्रतिरोधी निर्माण पद्धतियां अपनाने में प्रशिक्षित होकर ही वे जान–माल की क्षति को कम कर सकते हैं।

उत्तराखंड में आफत की बारिश, दूसरे दिन भी बंद रहा बदरीनाथ हाईवे

यात्रियों की भूस्खलन के कारण बढ़ी मुश्किलें

देहरादून। **संवाददाता**

चार धाम यात्रा मार्गों में भूस्खलन के कारण यात्रियों की मुश्किलें बनी हुई हैं। चमोली के लामबगड़ में भूस्खलन से बंद बदरीनाथ राजमार्ग शुक्रवार को भी नहीं खुल पाया, जबकि उत्तरकाशी के चुंगी बड़ेथी में गंगोत्री राजमार्ग तीन घंटे बंद रहा। लामबगड़ में लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने के काम पर जुटा है। यहां पर किसी तरह यात्रियों की पैदल आवाजाही ही सुचारु हो पाई है।

वाहनों के लिए मार्ग शनिवार शाम तक ही खुलने की संभावना है। खुद के वाहनों से बदरीनाथ की यात्रा करने वालों के सामने

मुश्किल है। ऐसे करीब एक हजार यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।

पैदल मार्ग तैयार होने पर करीब एक हजार यात्रियों को लामबगड़ भूस्खलन जोन से आवाजाही कराई गई। केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे दिनभर सुचारू रहे। चमोली के लामबगड़ में गुरुवार की सुबह बदरीनाथ हाईवे पर चट्टान का मलबा गिरने से सड़क बंद हो गई थी।

बीते दिन बारिश के चलते सड़क को खोलने का काम शुरू नहीं हो पाया था। शुक्रवार को मौसम साफ होने के बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। यात्रियों की पैदल आवाजाही के लिए लामबगड़ में अलकनंदा नदी के किनारे ही पैदल मार्ग का निर्माण किया गया।

बदरीनाथ जाने वाले यात्रियों ने पांडुकेश्वर और लामबगड़ में अपने वाहन छोड़कर यहां से पैदल ही आवाजाही की। उधर मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटे में पहाड़ों में कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है।

आपदा प्रभावित आराकोट और घाट को केंद्रीय टीम ने लिया जायजा

केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने शुक्रवार को उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित आराकोट और चमोली के घाट क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। सात सदस्यीय टीम ने आराकोट के मोल्डी गांव का दौरा कर प्रभावितों से हालचाल जाना। आराकोट राहत कैंप में रह रहे प्रभावितों से भी केंद्रीय टीम के सदस्यों ने बातचीत की।

कुमाऊं विवि के कॉलेजों में नौ सितंबर को होंगे छात्रसंघ चुनाव

संवाददाता नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसरों व संबद्ध कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव तथा छात्र महासंघ चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। विवि के परिसरों व संबद्ध कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव अधिसूचना तीन सितंबर को जारी की जाएगी, जबकि मतदान, मतगणना व चुनाव परिणाम की घोषणा नौ सितंबर को की जाएगी। दस हजार से कम छात्र संख्या वाले कॉलेज में प्रत्याशी प्रचार में अधिकतम 25 हजार व इससे अधिक छात्रसंख्या वाले कॉलेजों के प्रत्याशी 50 हजार खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए प्रो. अजय अरोड़ा के संयोजकत्व में नौ सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है। साफ किया गया है प्रत्याशी सिर्फ हस्तनिर्मित प्रचार सामग्री का प्रयोग कर सकेंगे। कुमाऊं विवि छात्र परिषद का चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है।

एक महीने से अंधेरे में डूबा है पलसारी तोक

संवाददाता उत्तरकाशी। भटवाड़ी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सिल्ला के पलसारी नामक तोक में बीते एक महीने से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। पीएमजीएसवाइ विभाग द्वारा सिल्ला गांव के लिए सड़क निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन सड़क और अतिवृष्टि के कारण सड़क जगह–जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जिसके कारण सड़क टूटने से गांव को जाने वाले विद्युत तारें और विद्युत पोल टूट गए हैं। स्थानीय ग्रामीण महेश पंवार, मान सिंह, राजेंद्र सिंह और विरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में बीते एक महीने से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। जंगल क्षेत्र से सटे होने के कारण रात के दौरान गांव में अंधेरा फैल जाता है, और ग्रामीणों को आसपास जंगली जानवरों का भय सता रहा है।

ऊर्जा निगम के विरोध में पंचायत की योजना

किसान यूनियन की आज होगी पंचायत

नारसन। **संवाददाता**

नारसन क्षेत्र में ऊर्जा निगम की छापेमारी के विरोध में किसान यूनियन की शनिवार को पंचायत होगी। इसमें किसानों की परेशानी को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं किसानों ने कहा कि ऊर्जा निगम को किसानों से कम दरों पर बिजली के बिलों की वसूली करनी चाहिए। कहा कि यदि किसानों की समस्या पर ऊर्जा निगम ने ध्यान नहीं दिया तो किसान आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल महामंत्री संजय चौधरी ने कहा कि इन दिनों किसान आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। किसान के पास इसके अलावा आय का कोई दूसरा स्त्रोत भी नहीं है। वहीं लगातार महंगाई बढ़ रही है।

सरकार टैक्स में बढ़ोत्तरी कर रही है, लेकिन किसानों की फसलों का वाजिब दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों को परेशान करने के लिए ऊर्जा निगम के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन इसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बिजली की दरों को चार वर्गों में बांटना चाहिए। जिसमें किसानों को सबसे निचले वर्ग में रखा जाए। किसानों से कम दरों पर बिजली का बिल वसूल किया जाए।

वहीं गढ़वाल महामंत्री अरविंद राठी ने बताया कि शनिवार को कस्बे में ही स्थित विद्युत उपकेंद्र पर किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर संदीप कुमार, धर्मेंद्र, अमित, प्रदीप, प्रताप, मोहसिन, खलील अहमद, तहसीन आदि मौजूद रहे।

बकाया भुगतान नहीं तो शुरू होगा धरना

झबरेड़ा। शुक्रवार को क्षेत्र के गांव कुरसल्ली खानमपुर में भारतीय किसान यूनियन (तोमर) ने गन्ना भुगतान को लेकर एक बैठक आयोजित की। जिसका संचालन मनीष कुमार ने किया और अध्यक्षता प्रधान पंजाब सिंह ने की। बैठक में झबरेड़ी कला कसौली भिस्तीपुर आदि गांव के लोगों ने हिस्सा लिया।